डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 सितम्बर, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 सितम्बर, 2025

| वर्ष 69 | अंक 08 | भोपाल | 16 सितम्बर, 2025 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश सरकार किसानों के साथ किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जिले में खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने के दिये निर्देश

खेतों में जाकर खराब हुई सोयाबीन की फसल का मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लिया जायजा

भोपाल :प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और हम किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाजापुर जिले की पोलायकलां तहसील के ग्राम खड़ी में विभिन्न कारणों से खराब हुई सोयाबीन की फसल के अवलोकन के बाद किसानों को यह भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाजापुर कलेक्टर सहित प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने के निर्देश दिये। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, विधायक श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, श्री अरूण भीमावद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराज सिंह सिसोदिया एवं डॉ. रवि पाण्डेय भी इस अवसर पर मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान चौपाल में कहा कि बारिश कम होने एवं कीट प्रकोप के कारण जहां-जहां भी सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है, उसका पूरा सर्वे कराया जायेगा, किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों को अधिकतम लाभ दिया जायेगा। किसानों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए केन्द्र एवं राज्य की सरकार लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कलेक्टर शाजापुर को निर्देश दिये कि जिन किसानों को पिछले वर्षों की बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनके प्रकरणों का निराकरण कराएं। आने वाले समय में शाजापुर जिले के किसानों को नर्मदा-पार्वती-चंबल-कालीसिंध लिंक परियोजना से पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे गरीब किसानों के जीवन में बदलाव आएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देशी गाय पालन को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई कामधेनु योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना में किसानों से गाय का दूध क्रय किया जायेगा। उन्होंने 25 गाय के पालन पर लगने वाली राशि 40 लाख पर सरकार द्वारा 10 लाख रूपये का अनुदान भी दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गायों के लिए गौशालाएं भी बनाई जायेगी। गौशालाओं को गायों के रखरखाव के लिए 40 रूपये प्रति गाय की दर से अनुदान दिया जायेगा। पांच हजार से अधिक पशु रखकर गौशाला संचालित करने पर भूमि भी उपलब्ध कराई जायेगी। इसी तरह क्षेत्र में विचरण कर रहे वन्यप्राणियों हिरण, नील गाय आदि के समुचित व्यवस्थापन के निर्देश भी वन विभाग को दिये। उन्होंने कहा कि किसान बिना किसी चिंता के अपनी फसलों का उत्पादन प्राप्त करें और खुशहाल बनें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "एक बगिया माँ के नाम" योजना के बारे में बताया और कहा कि किसानों को एक एकड़ जमीन में फलोद्यान लगाने पर प्रथम वर्ष 2 लाख रूपये तथा इसके अगले वर्ष 55 हजार रूपये इस प्रकार 3 वर्ष तक अनुदान दिया जायेगा।

कपास उत्पादन को प्रदेश सरकार प्रोत्साहित करेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए धार जिले के बदनावर में "पीएम मित्रा" औद्योगिक पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जिसका 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि धार जिले सहित मालवा निमाड़ अंचल के कपास उत्पादक किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगा।

किसान से नुकसान की जानकारी ली

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम खड़ी के किसान श्री परवत सिंह बगाना के निवास पर जाकर उनसे सोयाबीन की खराब हुई फसल से हुए नुकसान की जानकारी ली।

राष्ट्रपति ने दिलाई उपराष्ट्रपति को शपथ

नई दिल्ली। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में श्री सी. पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
ई-8/77, शाहपुरा भोपाल - 462039

वार्षिक साधारण सभा की सूचना

समस्त सदस्य, सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 25.03.1958) की 54 वीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25 सितम्बर 2025 को पूर्वान्ह 11:30 बजे, स्थान - म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई-8/77, शाहपुरा, भोपाल में आयोजित की गई है। गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक साधारण सभा आधे घंटे हेतु स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर, पूर्वान्ह 12:00 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

टीप :- सभी सदस्यों को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। अप्राप्ति की स्थिति में इस विज्ञापन को ही सूचना जाना जावे।

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश की सभी पैक्स समितियां डब्ल्यू.डी.आर.ए. की सदस्य बनेंगी : मंत्री श्री सारंग

सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय विविधीकरण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल :सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था से गांव व किसान को जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो जन-धन योजना लागू की है, इसका मुख्य उद्देश्य गांव व किसान को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसके सकारात्मक परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व एवं केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में निरंतर ''सहकार से समृद्धि'' के मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इसका अनुसरण करते हुए हम स्वर्णिम मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नवाचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए प्रदेश की प्रगति के लिये काम कर रहे हैं। मंत्री श्री सारंग अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय विविधिकरण पर अपेक्स बैंक, सहकारिता विभाग एवं विनियामक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जब तक अर्थव्यवस्थां आम आदमी के दरवाजे से नहीं निकलेगी, तब तक मजबूती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम किसानों को समृद्ध करना चाहते हैं, तो पहले हमें पैक्स (प्राथमिक कृषि सहाकारी समितियों) को समृद्ध बनाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। यह कार्यशाला निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी।

श्री सारंग ने कहा कि जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे मध्यप्रदेश की प्रत्येक पैक्स को डब्ल्यू.आर.डी.ए. (भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण) का सदस्य बनाने के प्रयास आज से ही आरंभ कर दें, जिससे कि आगे चलकर प्रदेश के किसानों को दूरदराज अंचलों में परेशान न होना पड़े व अपने नजदीकी डब्ल्यू.आर.डी.ए. के सदस्य वेयर हाउस में अपनी उत्पाद को सुरक्षित रख लाभान्वित हों, जब तक भण्डारण व्यवस्थित नहीं होगी, तब तक किसानों को उसका फायदा नहीं मिल सकेगा।

कार्यशाला में श्री सारंग ने अपेक्स बैंक द्वारा प्रकाशित मानक परिचालन प्रक्रिया वेयर हाउसिंग डेव्हलेपमेंट एण्ड रेग्यूलेटरी अथॉरिटी की योजनान्तर्गत वेयर हाउस पंजीकरण की पुस्तक का विमोचन भी किया तथा प्रदेश में गोदाम बनाने की योजना पर कार्य करने के लिये स्टेट वेयर हाउसिंग प्रबंध संचालक श्री अनुराग वर्मा, म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन तथा सहकारिता विभाग के नवाचार प्रकोष्ठ के संयुक्त आयुक्त श्री महेन्द्र दीक्षित को अधिकृत किया।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान हम किसानों को प्रशिक्षित करें कि वे अपने उत्पाद को कैसे बेहतर ढंग से रख सकते हैं और डिजीटली किस प्रकार बेच सकते हैं, आज की यह कार्यशाला एग्रो प्रोसेसिंग व मार्केटिंग की दिशा में अत्यन्त उपयोगी है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रकार की कार्यशाला हम संभाग व जिला स्तर पर भी आयोजित करेंगे।

कार्यशाला में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, डब्ल्यू.डी. आर.ए. ने कहा कि वर्ष 2051 तक हमारे देश की जनसंख्या 170 करोड़ हो जायेगी व मध्यप्रदेश की लगभग 12 करोड़, जो देश का लगभग 6.3 प्रतिशत होगी। मध्यप्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 338 लाख मी.टन है, जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 12.10 प्रतिशत है। भारत वर्ष 2051 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। उन्होंने कहा कि इस मान से प्रदेश में वेयर हाउस के गोदामों के लिये एक सुनियोजित योजना बनाने की दिशा में प्रयास किये जायें।

सी.डब्ल्यू.सी. क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रामकुमार ने बताया कि यदि केन्द्रीय वेयर हाउसिंग में डब्ल्यू.डी.आर.ए. के अन्तर्गत देश के 50 हजार गोदाम यदि रजिस्टर्ड हो जायें तो किसान आपके द्वार तक आ जायेंगे। इससे आपकी साख भी बढ़ेगी और किसान के साथ आप भी हमारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, हमारा उद्देश्य वेयर हाउस केन्द्रों को लाभ का केन्द्र बनाना है। इससे किसानों के उत्पाद सुरक्षित होंगे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है।

कार्यशाला में श्री विनीत गुप्ता, नेशनल ई-रिपोजिटरी लिमिटेड, श्री जसवीर गोदारा, एवीपी सीसीआरएल, श्री संजय अग्रवाल ने अपनी डिजीटल व्यवसाय प्रणाली पर विचार व्यक्त किये।

कार्यशाला में सहकारिता विभाग के संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त, जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वेयर हाउस व एफपीओ के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समीक्षा

भोपाल :सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपेक्स बैंक, भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नियुक्तियों, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति, खरीफ 2025-26 में अल्पावधि फसल ऋण वितरण, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना सहित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ 2025-26 के लिए समय पर अल्पावधि फसल ऋण वितरण सुनिश्चित हो तथा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पैक्स समितियों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और पैक्स कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया को गति देने पर विशेष बल दिया।

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड संचालन को और सरल एवं सुलभ बनाने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि किसान हितैषी नीतियों का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब जिला सहकारी बैंक मजबूत स्थिति में कार्य करें। इसलिए कमजोर जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और उसे जल्द लागू किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, नाबार्ड की सीजीएम श्रीमती सी. सरस्वती, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक (अपेक्स बैंक) श्री मनोज गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक राज्य

भोपाल :मध्यप्रदेश देश में सब्जी उत्पादन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में किसानों द्वारा 12 लाख 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन टमाटर का है, उल्लेखनीय मध्यप्रदेश टमाटर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में 2024-25 में एक लाख 27 हजार 740 हैक्टर में टमाटर की खेती की गई है इसमे 36 लाख 94 हजार 702 मीट्रिक टन का उत्पादन संभावित है। विगत 4 वर्षों में प्रदेश में टमाटर के रकबे में 16,776 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वर्ष 21-22 में प्रदेश में 1,10,964 हेक्टेयर में किसानों द्वारा टमाटर की खेती की गई थी जो वर्ष 24-25 में बढ़कर 1 लाख 27 हजार 740 हेक्टेयर हो गया है, जो बाजार में टमाटर की मांग और प्रदेश के टमाटर की पहचान का ही परिणाम है। मध्यप्रदेश के टमाटर की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहुत माँग है। किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं का परिणाम है कि टमाटर का उत्पादन सब्जियों में सर्वाधिक 28.92 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों की औसत उत्पादकता 15.02 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 26 लाख 91 हजार हेक्टर में से प्रदेश में किसानों द्वारा 12 लाख 40 हजार हेक्टेयर में 245 लाख 98 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन कर देश में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। सब्जियों फसलों में टमाटर, धनिया और लहसुन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है।

कुछ वर्षों से किसानों में टमाटर उत्पादन के प्रति आकर्षण बढ़ा है। राज्य सरकार भी टमाटर के बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। टमाटर पर आधारित लघु उद्योगों की संख्या भी बड़ी है। PMFME योजना से किसानों को फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट लगना आसान हुआ है।

अनूपपुर जिले के किसानों ने टमाटर उत्पादन में रचा नया इतिहास

अनूपपुर जिले के 15 हजार किसानों ने टमाटर की खेती कर एक लाख 40 हजार मीट्रिक टन टमाटर की रिकॉर्ड पैदावार की है। जिले के तीन प्रमुख क्लस्टर जैतहरी, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ में टमाटर की खेती व्यापक रूप से की जा रही है। इससे लगभग 15,500 किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। जिले में हाइब्रिड एवं स्थानीय किस्मों के टमाटर की खेती की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बीज ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर 50-50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों की लागत कम और उत्पादन के साथ आय बेहतर हुई है। अनूपपुर जिले का टमाटर मध्यप्रदेश के शहडोल, रीवा और सतना सहित छत्तीसगढ़ के रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों तक भेजा जा रहा है। इससे किसानों को बाजार की उपलब्धता के साथ-साथ बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। किसानों की आय वृद्धि के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर विपणन सुविधा भी उद्यानिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। टमाटर की खेती में प्रति हेक्टेयर 50 से 60 हजार रुपए की लागत आती है। इससे किसानों को डेढ़ से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा प्राप्त हो रहा है। प्रति एकड़ के हिसाब से यह मुनाफा एक लाख रुपए तक पहुंच रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

सहकार से समृद्धि : युवाओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम

भोपाल, भारत सरकार, सहकारिता विभाग के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के मार्गदर्शन में युवाओं के लिए सहकारिता संबंधी ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

19 अगस्त 2025 को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नौगांव में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को सहकारिता की अवधारणा, महत्व, रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने "सहकार से समृद्धि" की अवधारणा पर बल देते हुए युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

इसी क्रम में, दूसरा कार्यक्रम25 अगस्त 2025कोसहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जबलपुरके तत्वावधान में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रमपीएम श्री GHSS सालीवाड़ा, जबलपुरमें आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 50–60 स्कूल के विद्यार्थियोंने भाग लिया। विद्यार्थियों को सहकारिता की मूलभूत पृष्ठभूमि, सिद्धांत और उद्देश्य समझाए गए। उन्हें बताया गया कि भविष्य में सहकारिता किस प्रकाररोजगार, उद्यमिता एवं सामूहिक समृद्धिका माध्यम बन सकती है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:

- सहकारिता की पृष्ठभूमि, सिद्धांत और उद्देश्य पर चर्चा।
- युवाओं को सहकारिता में भागीदारी एवं रोजगार अवसरों से परिचित कराना।
- भविष्य में सहकारिता क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर विचार-विमर्श।
- "सहकार से समृद्धि" एवं "बिना सहकारिता, समृद्धि नहीं" के प्रेरक संदेशों द्वारा युवाओं को जागरूक करना।

ये कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025के अंतर्गत आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य युवाओं, विशेषकर कॉलेज एवं स्कूल स्तर पर, सहकारिता की प्रासंगिकता, संभावनाओं और करियर अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग इस पहल के माध्यम से नई पीढ़ी को सहकारिता क्षेत्र मेंरोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर कर रहा है।

मंत्री श्री सारंग ने की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ की समीक्षा

भोपाल :सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आवास संघ को एक सशक्त निर्माण एजेंसी के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस और दूरदर्शी कार्ययोजना तैयार की जाए।

मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर उनकी निधि से किए जाने वाले निर्माण कार्य आवास संघ को दिए जाने हेतु आग्रह करें। उन्होंने कहा कि "सहकारिताओं के बीच सहकार" की भावना को मूर्त रूप देते हुए सहकारिता विभाग के अंतर्गत राज्य संघ, उपभोक्ता संघ एवं अन्य सहकारी संस्थाओं से संबंधित सभी

निर्माण कार्यों के लिए आवास संघ को नोडल एजेंसी बनाया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एम-पैक्स से जुड़े निर्माण कार्य भी आवास संघ को ही सौंपे जाएं। उन्होंने आवास संघ की गतिविधियों के विस्तार के लिए सभी सहकारी सोसाइटियों को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस दिशा में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता श्री मनोज पुष्प, उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा, प्रबंध संचालक आवास संघ श्री विश्वकर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सीपीपीपी मॉडल से उपभोक्ता संघ को मिलेगी नई ऊर्जा : मंत्री श्री सारंग

मंत्री ने की राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ता संघ को आर्थिक रूप से सशक्त और प्रासंगिक बनाने के लिये अभिनव कदम उठाने होंगे। संघ को पुनर्जीवित करने के लिये सीपीपीपी (को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को अपनाया जाए, जिससे संघ की व्यावसायिक गतिविधियों में आधुनिकता और प्रतिस्पर्धात्मकता आ सकेगी।

मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ता संघ को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके अंतर्गत बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ कार्य करने की संभावनाओं को तलाशा जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित उपभोक्ता केंद्रों को बहुउद्देशीय बनाया जाए, क्योंकि ये केंद्र शहरों की प्रमुख लोकेशन्स पर स्थित हैं और बड़े ब्रांड्स को जोड़ने के लिये आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।

बैठक में मंत्री श्री सारंग ने उपभोक्ता संघ की वर्तमान आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, मानव संसाधन, और व्यवसाय वृद्धि की संभावनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि उपभोक्ता संघ को 'सहकारिताओं से सहकार' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रदेश की अन्य सहकारी संस्थाओं के साथ व्यवसायिक गतिविधियों को जोड़ने की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

खाद्यान्न उपार्जन से संबंधित आवश्यक सामग्रियों के प्रदाय के लिए उपभोक्ता संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के विषय पर भी चर्चा हुई। सुझाव दिया गया कि पैक्स और विपणन समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान उपार्जन में उपयोग होने वाली सामग्रियां विभिन्न जिलों में उनकी मांग के अनुसार उपभोक्ता संघ उपलब्ध कराए। इससे संघ को प्राप्त होने वाला मार्जिन उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और साथ ही उपार्जन करने वाली समितियों को पूरे प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सामग्रियां न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्री श्री सारंग ने विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी उपभोक्ता संघ को पुनः सक्रिय और प्रगतिशील बनाने के लिये हर स्तर पर ठोस और दूरगामी कदम उठाए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक उपभोक्ता संघ श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पायलेट प्रोजेक्ट

भोपाल: मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है और अब इस कड़ी में सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन फर्टीगेशन सिस्टम तकनीक का विकास किया गया है जो उद्यानिकी फसलों के लिए वरदान सिद्ध होगा। इस तकनीक के माध्यम से उद्यानिकी फसलों को सिंचाई के लिए जल और उर्वरकों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुपम राजन ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत "उद्यानिकी फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन फर्टीगेशन सिस्टम" विषय पर भोपाल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बताया कि प्रदेश में उद्यानिकी के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सूक्ष्म सिंचाई एवं सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन फर्टीगेशन

सिस्टम पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। इसकी सफलता पर उद्यानिकी के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के संबंध में लगातार फीडबैक प्राप्त कर परियोजना में आवश्यक सुधार किये जाएंगे। आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रीति मैथिल ने कहा कि यह तकनीक आधुनिक बागवानी खेती के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस तकनीक का उपयोग अनेक देशों में किया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके लिए प्रदेश के किसानों को जागरूक बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) के माध्यम से भारतीय सहकारी क्षेत्र के उत्पादों/सेवाओं का वैश्विक विस्तार

नई दिल्ली:भारत सरकार सहकारी क्षेत्र को वैश्विक व्यापार से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में बहु-राज्य सहकारी समितियां (MSCS) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत**राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL)**की स्थापना की गई है। यह समिति भारतीय सहकारी क्षेत्र की सामूहिक ताकत का उपयोग करते हुए किसानों, उत्पादकों और सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने का कार्य करेगी। इससे न केवल निर्यात में वृद्धि होगी बल्कि सहकारी उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलेगा।

NCEL का मुख्य उद्देश्य भारतीय सहकारी क्षेत्र को एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से:

- अधिशेष उत्पादों और सेवाओं का **निर्यात** किया जा सके।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **ब्रांड पहचान** बनाई जा सके।
- उत्पादकों को **उच्चतम मूल्य** प्राप्त हो।
- **कृषि और गैर-कृषि उत्पादों** की निर्यात क्षमता बढ़े।
- **बाज़ार की जानकारी, वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन** उपलब्ध कराया जा सके।
- NCEL बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। इसमें शामिल हैं:

खरीद एवं भंडारण:किसानों और सहकारी समितियों से उत्पादों की खरीद कर उनका वैज्ञानिक ढंग से भंडारण।

प्रसंस्करण:आधुनिक तकनीक से उत्पादों का मूल्य संवर्धन।

पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग:वैश्विक मानकों के अनुरूप आकर्षक पैकेजिंग और भारतीय सहकारी उत्पादों की ब्रांड पहचान।

प्रमाणीकरण एवं अनुसंधान:अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने हेतु प्रमाणन और निरंतर शोध कार्य।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:सहकारी समितियों और किसानों को आधुनिक व्यापार और निर्यात संबंधी प्रशिक्षण।

वित्तीय एवं तकनीकी सहायता:वित्तीय व्यवस्था और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

सदस्यता पात्रता एवं वर्तमान स्थिति

NCEL में सदस्यता के लिए कोई भी बहु-राज्य सहकारी समिति या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समिति पात्र है। अब तक**11,034 सहकारी समितियों**को NCEL की सदस्यता दी गई है। इनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	सहकारिता का प्रकार	संख्या
i.	पैक्स और अन्य प्राथमिक सहकारी समितियाँ (वर्ग–5)	**10,793**
ii.	तहसील/जिला स्तरीय सहकारी समितियाँ (वर्ग–4)	**216**
iii.	बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (वर्ग–3)	**10**
iv.	राज्य स्तरीय सहकारी समितियाँ (वर्ग–2)	**10**
v.	प्रमोटर सहकारी समितियाँ/संगठन (वर्ग–1)	**5**
	कुल	**11,034**

NCEL द्वारा अब तक निर्यात की गई कृषि वस्तुओं की कुल मात्रा और मूल्य इस प्रकार हैं:

कुल मात्रा: 13,49,831.05 MT

कुल मूल्य: रु. 54,03,01,47,854 (लगभग रु. 5,403.01 करोड़)

इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि सहकारी समितियों की सामूहिक शक्ति अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है

भारत सरकार सहकारी निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने हेतु विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के माध्यम से कार्य कर रही है। दूतावासों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजार अवसरों की जानकारी NCEL को उपलब्ध कराएं तथा संबंधित देशों के आयातकों को NCEL से जोड़ें।

NCEL द्वारा किए गए प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं:

जाम्बिया गणराज्य: सहकारिता मंत्रालय और लघु एवं मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय के साथ एमओयू।

सेनेगल सरकार: उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के साथ एमओयू।

इंडोनेशिया: सिंटन वैंटेज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और PT सिंटन सुरिनी नुसंतारा के साथ एमओयू।

इन समझौतों से न केवल नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे, बल्कि सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

जिलों में उर्वरक वितरण में अव्यवस्था के लिए कलेक्टर होगें उत्तरदायी - मुख्यमंत्री

जिला प्रशासन, उर्वरक उपलब्धता और वितरण के संबंध में किसान संगठनों से निरंतर सम्पर्क और संवाद बनाए रखें

उर्वरक वितरण व्यवस्था की हो सघन मॉनीटरिंग और अनुचित गतिविधियों पर करें कठोर कार्यवाही

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की अतिवृष्टि तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिलों में उर्वरक वितरण के संबंध में जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्था बनाए। उपलब्ध उर्वरक की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से निरंतर संवाद और संपर्क में रहे। उर्वरक वितरण की व्यवस्था में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। जिलों में यदि उर्वरक वितरण को लेकर अव्यवस्था होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टर उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और जिलों में उर्वरक वितरण की स्थिति की बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिले के कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

किसानों को जिले में उपलब्ध उर्वरक की वास्तविक स्थिति से निरंतर करावाये अवगत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में उर्वरक उपलब्धता की सघन समीक्षा की जाए। साथ ही जिले में उपलब्ध उर्वरक के स्टॉक की जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी साझा करें, इससे किसानों को जिले में उर्वरक उपलब्धता की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन डबल लॉक, पैक्स और निजी विक्रय केंद्रों का आकस्मिक सत्यापन और उनकी मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से करें। अतिरिक्त विक्रय केन्द्र की आवश्यकता होने पर उनका संचालन तत्काल आरंभ किया जाए। कृषि, सहकारी बैंक, विपणन संघ के अधिकारी निरंतर सम्पर्क में रहें।

उर्वरक से संबंधित अवैध गतिविधियों के लिए हुईं 53 एफ.आई.आर और 88 लायसेंस किए निरस्त

बैठक में खरीफ 2025 के लिए यूरिया, डी.ए.पी, एन.पी.के, एस.एस.पी, एम.ओ.पी तथा डी.ए.पी + एन.पी. के की उपलब्धता, ट्रांजिट की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही नेनो एवं जैविक उर्वरक वितरण कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बताया गया कि उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और नकली उर्वरक आदि से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 53 एफ.आई.आर दर्ज की गई और 88 लायसेंस निरस्ती, 102 लायसेंस निलंबन सहित 406 विक्रय प्रतिबंधित की कार्यवाही की गई।

उर्वरक की बेहतर वितरण व्यवस्था में हुए नवाचारों का करें अनुसरण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में धार, दमोह, जबलपुर और रीवा जिले के कलेक्टरों से चर्चा की। दमोह कलेक्टर ने बताया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सतत् सम्पर्क और संवाद सुनिश्चित करते हुए वितरण व्यवस्था में उनका सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही टोकन वितरण और उर्वरक वितरण को अलग-अलग किया गया है। टोकन तहसील कार्यालय से बांटे जा रहे हैं और वितरण विक्रय केन्द्रों से किया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने बताया कि किसानों के लिए टोकन वितरण की व्यवस्था फोन कॉल द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। उर्वरक वितरण केन्द्रों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड न पर टोकन नंबर प्रदर्शित कर उर्वरक वितरण किया जा रहा है। डिस्प्ले बोर्ड पर जिले में उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा भी प्रदर्शित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य जिलों को भी इस प्रकार के नवाचार अपनाने के निर्देश दिए।

बीज संघ ने किया उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का उत्पादन प्रारंभ

मंत्री श्री सारंग की अध्यक्षता में सहकारी बीज उत्पादक-विपणन संघ की बैठक

भोपाल :सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित के संचालक मंडल की बैठक की। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए संघ द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान प्रजनक बीज उठाव एवं वितरण, आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन और विपणन की वर्तमान स्थिति तथा आगामी लक्ष्यों की समीक्षा की गई। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की वास्तविक मांग के अनुरूप बीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि जिन बीजों एवं ब्रांड की अधिक मांग है, उनके उत्पादन एवं आपूर्ति पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि 'एमपी चीता' ब्रांड को एक सशक्त मार्केटिंग रणनीति के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए, जिससे यह किसानों के बीच एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण ब्रांड के रूप में स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि चिन्हित फसलों और बीजों पर फोकस करते हुए, हॉर्टिकल्चर (बागवानी) फसलों को भी बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। बैठक में बताया गया कि बीज संघ ने किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इन बीजों से बेहतर पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त होगी। मंत्री श्री सारंग ने इस पहल को कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम बताते हुए इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि बीज उत्पादन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिये है कि रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसके लिए आवश्यकतानुसार मैन पावर भी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन एवं गुणवत्ता संवर्धन के लिए एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाए, जिसमें विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। इससे बीजों की ब्रांड वैल्यू और गुणवत्ता सुधार के नए आयाम जुड़ सकेंगे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डीपी आहूजा, कृषि सचिव श्री निशांत वरवड़े, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, बीज संघ के प्रबंध संचालक श्री महेंद्र दीक्षित सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं संघ के संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

भारत के सहकारी निर्यात को नई ऊंचाई पर ले जाएगा NCEL–APEDA का सहयोग

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने सहकारी आधारित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

यह MoU सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है

NCEL के नेटवर्क को APEDA की निर्यात सुविधा से जोड़ने से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूती मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत करेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय, सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कार्य कर रहा है

NCEL और APEDA क्षमता निर्माण, गुणवत्ता अनुपालन, अवसंरचना सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और बाजार स्थिति निर्माण पर विशेष ध्यान देंगे

यह MoU एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत के सहकारी आधारित कृषि निर्यात को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है। यह समझौता ज्ञापन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में संपन्न हुआ जो सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की शक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस MoU पर APEDA की ओर से अध्यक्ष, श्री अभिषेक देव और NCEL की ओर से प्रबंध निदेशक, श्री अनुपोम कौशिक ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि NCEL के नेटवर्क को APEDA की निर्यात सुविधा से जोड़ने से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा, ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूती मिलेगी और यह नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भारत की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और सुदृढ़ करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय, सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के विज़न पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि NCEL और APEDA संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, निर्यात हेतु गुणवत्ता मानकीकरण, अवसंरचना सहयोग एवं पुनर्जीवन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और बाजार में स्थिति निर्माण, मार्केट इंटेलिजेंस एवं डेटा विश्लेषण तथा वस्तु-विशेष निर्यात रणनीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

डॉ. भूटानी ने कहा कि सहकारी समितियों को इस MoU के अंतर्गत संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात डोक्युमेंटेशन की समझ विकसित होगी। उन्होंने कहा कि APEDA की निर्यात सुविधा को NCEL के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर फलों, सब्जियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य, अनाज और पशु उत्पादों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा सकता है।

सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव श्री पंकज कुमार बंसल ने कहा कि यह MoU, APEDA की तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत सहयोग से NCEL को सशक्त बनाता है, जिससे इसके सदस्य निर्यात उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेंगे, नए बाजारों तक पहुँच बना सकेंगे और अपनी उपज के लिए प्रीमियम मूल्य सुरक्षित कर सकेंगे।

यह MoU एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। APEDA की अवसंरचना और बाजार पहुंच क्षमताओं को NCEL के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर यह साझेदारी किसान-सदस्यों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देगी, भारत के निर्यात पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी और नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप राष्ट्रीय विकास में सहकारी आंदोलन के योगदान को सुदृढ़ करेगी। NCEL की भूमिका को राष्ट्रीय अंब्रेला संगठन के रूप में और APEDA के बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन के दायित्व के साथ जोड़कर यह साझेदारी निर्यात तैयारी, ब्रांडिंग, अवसंरचना विस्तार और क्षमता निर्माण को गति प्रदान करेगी।

सहकारिताओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वस्तु सेवा कर (GST) दर में व्यापक कटौती

नई दिल्ली।केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में व्यापक कमी की घोषणा की है, जिससे सहकारी संस्थाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमों सहित 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को सीधा लाभ होगा। ये सुधार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे, उनके उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, उनके उत्पादों की माँग और उनकी आय बढ़ाएंगे। यह ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारिताओं को प्रोत्साहित करेगा और लाखों परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुएँ किफायती रूप से उपलब्ध कराएगा। जीएसटी दर में कटौती खेती और पशुपालन में लगी सहकारिताओं को लाभ पहुँचाएगी, टिकाऊ खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देगी और छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सीधा लाभ देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाये गये #NextGenGST रिफार्म का पूरे दुग्ध सहकारी क्षेत्र ने स्वागत किया है, जिसमें अमूल जैसे सबसे बड़े सहकारी ब्रांड भी शामिल हैं।

दुग्ध क्षेत्र में किसानों और उपभोक्ताओं को वस्तु सेवा कर में सीधे राहत दी गई है। दूध और पनीर, चाहे ब्रांडेड हों या बिना ब्रांड के, को जीएसटी से मुक्त किया गया है। मक्खन, घी और ऐसे ही अन्य उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तरों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इन उपायों से दुग्ध उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, दुग्ध किसानों को सीधी राहत मिलेगी और विशेषकर दूध प्रसंस्करण में लगी महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वयं सहायता समूह (SHGs) को मजबूती मिलेगी। किफायती दुग्ध उत्पाद घर-घर में आवश्यक प्रोटीन और वसा स्रोत उपलब्ध कराएंगे और दुग्ध सहकारिताओं की आय बढ़ाएँगे।

खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू वस्तुओं में बड़ी राहत दी गई है। चीज़, नमकीन, मक्खन और पास्ता पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जैम, जेली, खमीर, भुजिया और फलों का गूदा/जूस आधारित पेय पदार्थ अब 5% जीएसटी पर आएंगे। चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और कॉफी पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

कम जीएसटी से खाद्य पदार्थों पर घरेलू खर्च घटेगा, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में माँग बढ़ेगी और खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध सहकारिताओं की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण और दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताएँ तथा निजी डेयरियाँ मजबूत होंगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पैकिंग पेपर, डिब्बे और पेटियों (crates) पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सहकारिताओं और खाद्य उत्पादकों के लिए लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत कम होगी।

कृषि यंत्र क्षेत्र में, 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ट्रैक्टर अधिक किफायती होंगे और इसका लाभ केवल फसल उत्पादक किसानों को ही नहीं बल्कि पशुपालन और मिश्रित खेती करने वालों को भी मिलेगा, क्योंकि इनका उपयोग चारे की खेती, चारे के परिवहन और कृषि उत्पाद प्रबंधन में किया जा सकता है। ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य अनेक पुर्जों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे लागत और घटेगी और सहकारिताओं को सीधा लाभ होगा।

उर्वरक क्षेत्र में, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उल्टा कर ढांचा सुधरेगा, उर्वरक कंपनियों की इनपुट लागत घटेगी, किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी और बुवाई के समय पर किफायती उर्वरक उपलब्ध होंगे। इसका सीधा लाभ सहकारिताओं को होगा।

इसी प्रकार, बारह बायो-पेस्टीसाइड और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जैव-आधारित कृषि इनपुट अधिक किफायती होंगे, किसान रासायनिक कीटनाशकों से हटकर बायो-पेस्टीसाइड की ओर बढ़ेंगे, मिट्टी की सेहत और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी, और छोटे जैविक किसानों तथा एफपीओ (Farmer Produce Organisation) को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन के अनुरूप है और सहकारिताओं को भी लाभान्वित करेगा।

वाणिज्यिक वाहनों में, ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ट्रक भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं और लगभग 65–70% माल यातायात का वहन करते हैं। इससे ट्रकों की पूंजीगत लागत घटेगी, प्रति टन-किलोमीटर भाड़ा कम होगा और इसका प्रभाव कृषि उत्पादों की ढुलाई को सस्ता बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में दिखाई देगा।

विपणन सहकारी संस्थाओं के उत्थान हेतु इंदौर में संगोष्ठी सम्पन्न

इंदौर, सहकारिता के क्षेत्र में विपणन संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दिनांक 08 सितम्बर 2025 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में"विपणन सहकारी संस्था के उत्थान"विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम मेंउपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर श्री मनोज जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विपणन सहकारी संस्थाएँ किसानों को उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुँचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिलती है।

संगोष्ठी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट ने संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र निरंतर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन कौशल को उन्नत करने का प्रयास करता है।

देवी अहिल्या विपणन सहकारी संस्था के अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र पाटिल ने संस्थाओं की भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसानों के उत्पादों का संगठित विपणन, आधुनिक तकनीक का उपयोग एवं बाजार विस्तार ही संस्थाओं की प्रगति का आधार है। संस्था भविष्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और निर्यात क्षेत्र में भी सक्रिय होने की दिशा में कार्य करेगी।

संगोष्ठी में सहकारी जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विपणन सहकारी संस्थाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विचार-विमर्श किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत जबलपुर में सहकारी सेमिनार सम्पन्न

जबलपुर,अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाने हेतु गांधी स्मारक भवन, मझौली (जिला जबलपुर) में सहकारी सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार में जिले के सहकारी क्षेत्र से जुड़े अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने सहकारिता आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान प्रासंगिकता एवं भविष्य की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। यह रेखांकित किया गया कि सहकारी समितियाँ किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।जनप्रतिनिधियों एवं सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को नई तकनीक और डिजिटलीकरण से जोड़ना समय की आवश्यकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तथा सहकारिता"सबका साथ, सबका विकास"की अवधारणा को और अधिक सशक्त करेगी।कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों और नवाचारों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने सहकारिता के मूल मंत्र"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय"को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत बरगी में सहकारी सेमीनार संपन्न

जबलपुर, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर कृषि उपज मंडी बरगी में एक दिवसीय सहकारी सेमीनार का आयोजन सहकारिता विभाग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरगी विधायक श्री नीरज सिंह ने कहा कि"ऐसे आयोजन हमें अपनी सहकारी गतिविधियों की निष्पक्ष समीक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। उपलब्धियों और त्रुटियों की समीक्षा के बाद ही हम सहकारिता के विकास के लिए सार्थक योजनाएं बना सकते हैं। सहकारी समितियां वर्तमान आवश्यकताओं एवं आने वाली चुनौतियों से उबर कर नए विश्व निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती हैं।"

विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा गोटियां ने सहकारिता में नवाचार को समय की आवश्यकता बताया और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रमों की निरंतरता पर बल दिया। वहीं जनपद अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रकिरण गिरि गोस्वामी ने कहा कि सहकारिता गांव की संस्कृति में रची-बसी है और युवाओं की भागीदारी से ही सहकार से समृद्धि का सपना पूरा होगा।विशेष रूप से उपस्थित महंत श्री दयानन्द गिरी महाराज सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं सहकारी कार्यकर्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर पटले ने की। उन्होंने 'सहकारिता से समृद्धि' विषय पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सहकारिता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।सेमीनार का स्वागत भाषण वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रशासक, जिला सहकारी संघ जबलपुर ने दिया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री वी. के. बर्वे ने शासन की सहकारी नीतियों की जानकारी दी, वहीं इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राजेश मिश्रा ने किसानों को नैनो खाद की विशेषताओं से अवगत कराया।कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक डॉ. प्रशांत कौरव ने किया, जबकि आयोजन की व्यवस्था जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेयी एवं सहकारी प्रशिक्षक श्री जयकुमार दुबे ने की।अंत में आभार प्रदर्शन बैंक शाखा गोहलपुर की शाखा प्रबंधक श्रीमती आकांक्षा भारतद्वाज ने किया। कार्यक्रम में पैक्स समितियों, वनोपज समितियों, सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों, कृषक सदस्यों एवं कर्मचारियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत इफको ई-बाज़ार, मुरैना में वृहत सहकारी सम्मेलन आयोजित

मुरैना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर दिनांक 10 सितम्बर 2025 को इफको ई-बाज़ार, मुरैना में एक दिवसीय वृहत सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग, किसान एवं सहकारी संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता मात्र संगठन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला है। सहकारिता के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने किसानों से सहकारी समितियों के साथ जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

सम्मेलन में उपस्थित सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने हेतु युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, नवाचार अपनाने तथा आधुनिक तकनीक को सहकारी गतिविधियों में शामिल करने पर बल दिया।

इफको ई-बाज़ार प्रबंधन द्वारा कृषकों को नैनो यूरिया एवं अन्य नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के विशेषज्ञों ने शासन की नवीन सहकारी योजनाओं एवं सहकारी बैंकों की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को नई दिशा

पारंपरिक कला को नई पहचान देने दो माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ

भोपाल। प्रदेश के हस्तशिल्पियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी.एच.सी.डी.एस.) अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। इन कार्यक्रमों का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षण

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, ई-8/76 शाहपुरा, त्रिलंगा रोड, भोपाल में 13 अगस्त 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में चयनित हस्तशिल्पियों को मास्टर ट्रेनर सुश्री उजमा खान, श्रीमती देविका दभाड़े एवं श्रीमती शीबा बी प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

बरखेड़ा पठानी, भोपाल में 25 अगस्त 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक तथा गांधी भवन, भोपाल में 1 सितम्बर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक भी 50 दिवसीय डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। यहाँ चिन्हित हस्तशिल्पियों को मास्टर ट्रेनर श्रीमती दीपिका जड़िया, श्रीमती हुमा खान, सुश्री श्रेया पटेल एवं सुश्री फिरोज जहाँ प्रशिक्षण देंगी।

परिधानों पर विशेष फोकस

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हस्तशिल्पियों को दुपट्टा, सूट, साड़ी, कुशन कवर, बेडशीट, कुर्ता और रूमाल जैसे परिधानों एवं गृह सज्जा सामग्री पर आकर्षक कढ़ाई कर उन्हें बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने का कौशल सिखाया जा रहा है। इस पहल से पारंपरिक हस्तशिल्प को आधुनिक डिज़ाइन और तकनीक से जोड़ा जाएगा।

20 हजार हस्तशिल्पियों को लाभ

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि सी.एच.सी.डी.एस. योजना अंतर्गत प्रदेश के लगभग 20,000 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल उनके कौशल का विकास होगा बल्कि उन्हें आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

विशेष सहयोग

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता में श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, श्री सुभाष नंद तिवारी, एक्सपर्ट मार्केटिंग, प्रशिक्षण कार्यक्रम की पर्यवेक्षक श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव, सीड संस्था सचिव श्री धर्मेंद्र राजपूत, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा तथा सीड संस्था के कर्मचारियों का विशेष सहयोग उल्लेखनीय है।

मत्स्य सहकारी समिति दमानियां में सहकारिता एवं उद्यमिता पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

छतरपुर। सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव (जिला छतरपुर) द्वारा प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, दमानियां जिला निवाड़ी (म.प्र.) में एक दिवसीय शिक्षा-प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों से जुड़े सदस्यों को सहकारिता की बारीकियों, नवाचारों, योजनाओं एवं रोजगारोन्मुख अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराना रहा।

शिविर का संचालन केंद्र के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार ने किया, उन्होंने सहकारिता आंदोलन का इतिहास, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता तथा सरकार द्वारा सहकारी समितियों को सशक्त बनाने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सीएचसीडीएस, उद्यमिता (Entrepreneurship), कौशल उन्नयन, समितियों के संचालक मंडल के दायित्व और उनकी भूमिका संबंधी आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि

किस प्रकार सहकारी समितियां नवाचार अपनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकती हैं।

शिविर में समिति के अध्यक्ष श्रीमूलचंद केवट, सचिव श्रीलालाराम केवटसहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य, ग्रामीण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने इस प्रकार के प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताया और कहा कि इससे उन्हें अपने कार्यों के संचालन और समिति को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर मत्स्य विभाग टीकमगढ़ के मत्स्य निरीक्षक श्रीआर.पी. पटेलतथा सहकारिता विभाग टीकमगढ़ के सहकारी निरीक्षक श्री मनीष खरे की सक्रिय उपस्थिति और सहयोग सराहनीय रहा। दोनों अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों को मत्स्य पालन के आधुनिक तरीकों, सहकारिता से जुड़ने के लाभ और सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सुकलिया, जिला देवास में दिनांक 11 सितम्बर 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण वर्ग में समिति सचिव श्री संजय चौधरी, टेस्टर श्री कमल चौधरी तथा समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सहकारिता की पृष्ठभूमि, सहकारिता के सिद्धांत तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता के महत्व की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर समिति सचिव श्री संजय चौधरी ने समिति की कार्यप्रणाली से सभी को अवगत कराया तथा आभार व्यक्त किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।